सेवा से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रहमण्यन): (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित नीतियों नियमों तथा आदेशों आदि का सख्ती से तथा ठीक प्रकार से अनुपालन करने की हिदायत दी गई है ताकि मुकदमेबाज़ी कम से कम हो जाए। उन्हें अपने स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करने, दोष दूर करने के उद्देश्य से शिकायत प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने, नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा स्टाफ संबंधी सभी मामलों के निपटान के लिए समय मानक निर्धारित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मुकाबले अन्य न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटाने में लिए जा रहे समय की तुलना के लिए कोई तुलनात्मक अध्ययन हाथ में नहीं लिया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा स्थगन आदेश उसकी अपनी न्यायिक हैसियत से दिए जाते हैं। सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को न्यायाधिकरण में अपने मामलों का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार न्यायाधिकरण में उपाध्यक्ष तथा सदस्य के स्तर की रिक्तियों को यथासंभव शीघ्रता से भरने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ङ) न्यायाधिकरण के न्यायालय में एक सदस्य न्यायिक क्षेत्र से तथा दूसरा प्रशासनिक क्षेत्र से होता है। सेवारत/सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारी न्यायाधिकरण में उपाध्यक्ष तथा न्यायिक सदस्य के पदों पर पहले ही नियुक्त किए जा रहे हैं।

Reservation in promotion to OBCs

1481. SHRI JANARDAN YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide reservation in promotion to the OBCs; and

(b) if so, whether a Constitution Amendment Bill in this regard is likely to be introduced in the current session of Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Conditions for Allotment of Petrol Pumps

1482. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the conditions to be fulfilled by an allottee before starting a petrol pump;

(b) what is the minimum period of lease of land required for putting up a petrol pump;

(c) whether a petrol pump can be started on disputed land or land whose lease is only for three years; and

(d) if not, whether any petrol pump has been licensed in Bangalore District to start on a land having only 3 years' lease?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) In case of 'B' site retail cutlets, the dealer-select is required to procure a suitable plot of land of the required dimension in the advertised location. He has also to arrange for finance and develop all the other facilities except the storage tanks and dispensing unit which are provided by the oil companies.

(b) For a 'B' site retail outlet, the dealer-select is required to take land on lease for an initial period of 15 years with a renewal option thereafter for a minimum period of 5 years.

(c) No retail outlets are developed on disputed land as per existing policy. In exceptional cases, the land is taken on lease for a sharter period with renwal option, primarily from Government bodies.

(d) Yes, Sir. In one case in Bangalore Distt. a retail outlet has been allowed to be commissioned on a land leased for a period of 3 years. The lease agreement contains a renewal clause also.